विरुद्ध भविष्य निधि आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ग). भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उक्त प्रतिष्ठान की ओर इस समय जून, 1976 से लेकर 15 अप्रैल, 1977 तक (जब यह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिवालिया घोषित किया गया था) के भविष्य निधि अंशदानों की राशि बकाया है । जून, 1976 से अक्तूबर, 1976 तक की अवधि की देय राशियों की भूमि राजस्व की बकाया राशियों के रूप में वसूली के लिए कारंवाई आरम्भ की गई थी, परन्तु प्रतिष्ठान द्वारा दायर किए गए आवेदन-पत्र पर उसे उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया । इसके कारण इस प्रतिष्ठान के खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया जा सका । अब चूंकि कम्पनी दिवालिया हो गई है, इसलिए सांविधिक देय राशियों के लिए दावे सरकारी परिसमापक के पास दायर किए जाते हैं ।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन सांविधिक उपबन्धों के अनुपालन करना नियोजक का दायित्व है ।

New Steel Plants during Fifth Plan

596. SHRI GANANATH PRADHAN:
SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there are any proposals to set up new Steel Plants during the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the States in which these will be set up?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): (a) and (b). The three new steel plants are in the following stages of progress:

(1) Salam Steel Plant, Tamilnadu 1st stage - under implementation.

(2) Vijayanagar Steel Project, Karnataka: Detailed Project Report under consideration by SAIL.

(3) Visakhapatnam Steel Project, Andhra Pradesh—Detailed Project Report under preparation by the consultants.

पोस्टल मुहरों के निर्माण के लिए सप्लाई आदेश में कमी

507. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में प्रयोग होने वाली मुहरों की संख्या तथा किस्मों में हाल में कमी कर दी गई है जिसके फलस्वरूप पोस्टल सील्स सहकारी समिति, अलीगढ़ को उनके निर्माण हेतु सप्लाई आर्डर में भी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, किस किस्म की मुहरों को अब समाप्त कर दिया गया है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सहकारी समिति ने कटौती को बहाल करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संचार मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) जी हां ।

(ख) शाखा डाकघरों में तारीख की सीलों की जगह नाम की सीलें चालू की गई हैं। उप-डाकघरों और मुख्य डाकघरों में इस्तेमाल की जाने वाली सीलों की संख्या सीमित करके आपरेटरों की संख्या के बराबर कर दी गई है और एक बीमा सील भी इस्तेमाल की जाती है । ये सीलें उन पिछली सीलों की जगह इस्तेमाल की जाएगी जो विभागवार तैयार की गई थीं । डाक कर्मचारियों द्वारा भारी संख्या में सीलों का इस्तेमाल करने में व्यर्थ का काम कम करने और कार्य-कुशलता के अनुरूप खर्च में मितव्ययता लाने के लिए नये आदेश जारी किए गए हैं ।

(ब) सोसायटी की तरफ से ऐसा कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं आया, जिसने खास तौर पर यह मांग की हो कि सीलों में की गई यह कमी बहाल कर दी जाय। इसलिए उस पर कोई फैसला करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Continuation of Tripartite Apex Body

598. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether a tripartite Apex Body was formed to keep watch on the industrial relations in the country during emergency;

(b) whether the said Body still continues to function; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) A Bipartite (and not Tripartite) National Apex Body was formed during emergency.

(b) No.

(c) Does not arise.

Changes in Diplomatic Posts

599. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are planning for a change at high level diplomatic posts; and

(b) if so, when it will be given effect to?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) and (b). As the manning of high-level Diplomatic posts abroad is a matter of considerable importance, the question of sending appropriate persons from within the Foreign Service or from public life to represent the country is a matter that constantly engages the attention of Prime Minister and Foreign Minister. Changes are made from time to time in the public interest.

Passports Impounded during Emergency

600. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of passports impounded during emergency;

(b) how many of them belonged to people with political background;

(c) how many of them belonged to businessmen; and

(d) whether the persons in authority concerned have been proceeded against and the impounded passports have been returned?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) to (d). During the Emergency, the total number of persons whose passports were impounded or to whom passport facilities were denied, for political or economic reasons, by invoking the provision in the Passports Act, 1967 relating to the interest of general public was 2,023. The passports of 237 persons were impounded or passport facilities denied for political reasons, e.g. anti-Emergency activities. Passport facilities were withdrawn or withheld in 1,786 cases for economic reasons under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act. In 256 cases impounding and refusal orders have been cancelled. Passports have not yet been returned in the case of 1,767 persons as the matter is under consideration. The action taken to impound passports or withhold passport facilities was taken under the authority and with the approval of the Ministers concerned.